मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस चीज को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए एक आल इंडिया वेज बोर्ड बनाने के लिए कोई योजना बना रही है जिस से एम्प्लायर्स और एम्प्लायीज दोनों पर उन का निर्णय बाइंडिंग हो ? क्या ऐसा विचार सरकार का है ?

श्री हाथी : जी हां, ऐसा विचार चल रहा है।

'WORK TO RULE' BY POSTAL EMPLOYEES

+

*97. SHRI BENI SHANKER SHARMA :

SHRI D. C. SHARMA :

SHRI RAM KISHAN GUPTA :

SHRI R. K. SINHA :

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state :

(a) whether the Postal employees have started the 'work to Rule' campaign at the instance of the National Federation of Posts and Telegraphs Employees to protest against the victimization of the employees who took part in the strike on the 19th September, 1968;

(b) if so, to what extent it has affected the postal services; and

(c) the action proposed to be taken in the matter ?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (SHRI I. K. GUJRAL): (a) Though there was no official intimation from the NFPTE, some of the P&T Employees indulged in a go slow campaign from 20th to 27th September. It is seen from Press Reports that this was following a directive from NFPTE. This 'go-slow' was otherwise described as 'work-to-rule' by the Federation.

(b) This go-slow campaign affected the services only in a few bigger offices in Delhi, Calcutta and parts of Madhya Pradesh. In these places the delivery of mails was affected to some extent and there was also some accummulation of mails. At other stations the service was hardly affected.

The go-slow was again resumed between the 8th and 17th October in a few places following the hunger strike of the J.C.A. leaders in Delhi. The services were however not dislocated to any extent on this account.

(c) As a result of the action taken against officials neglecting their work, the situation soon returned to normal.

श्री वेणी शंकर शर्मा : अध्यक्ष महोदय, कल के अविश्वास प्रस्ताव पर हुई बहस के बाद मेरा यह प्रश्न कुछ पुराना सा हो जाता है किन्तु फिर भी मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जैसा अभी-अभी उन्होंने कहा है कि क्या कलकत्ते, दिल्ली और दूसरी जगहों में संचार व्यवस्था कुछ अंश तक ठप्प हो गई थी, मेरा कहना है कि जहां तक कलकत्ते का सवाल है वहां संचार व्यवस्था कुछ अंश तक नहीं बल्कि एक दम ठप्प हो गई थी और उसी समय उत्तर बंगाल में बाढ़ का ताण्डव नृत्य हो रहा था। तो क्या माननीय मन्त्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उन्होंने उत्तर बंगाल से सम्पर्क स्थापित करने के लिए बेतार की संचार व्यवस्था का काम क्यों नहीं लिया ?

श्री इ०कु०गुजराल: अध्यक्ष महोदय, आनरेबल मेम्बर दो चीजों को मिला रहे हैं। जो मैं ने जवाब दिया यह गो स्लो के मुताल्लिक दिया जो 20 सितम्बर से 27 सितम्बर और अक्तूबर में फिर हुआ था। स्ट्राइक की बात 19 सितम्बर वाली उस से अलग है। जो मैंने यह कहा कि काम में खास नुकसान नहीं हुआ तो मेरा मतलब गो स्लो के मुताल्लिक था। 19 सितम्बर की स्ट्राइक के मुताल्लिक नहीं था।

श्री वेणी शंकर शर्मा : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जहां तक 19 तारीख की टोकन स्ट्राइक का प्रश्न है उस में बहुत से लोगों पर कई प्रकार के चार्ज लगाये गये थे जिनमें बहुत से तो

वापस ले लिए गए हैं, और बहुत से अभी बाकी हैं, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि नियमानुसार कार्य की जो स्ट्राइक चल रही थी जिसमें डाकखाने वाले भी शामिल थे और जिस पर कुछ मुअत्तिली आदि की कार्यवाहियां की गई थीं, उन्हें वापस लिया गया है या नहीं ?

श्री इ० कु० गुजराल : अध्यक्ष महोदय, गो स्लो के मुताल्लिक बहुत कम लोगों के ऊपर ऐक्शन लिया गया था। कोई 200 के करीब ससपेंड किये गये थे और उस ऐक्शन को विदड्रा करने का सवाल नहीं पैदा होता क्योंकि कोई आदमी मुहकमें में रहते हुए मुहकमे का काम नहीं निभाता और लोगों को तकलीफ होती है तो यह ठीक नहीं है। जनता के हक में यह बात है कि सर्विस को चालू रखा जाय और जो अपना काम न करें उन को सजा दी जाय।

SHRI D. C. SHARMA : May I ask the hon. Minister how many unions there are among the post and telegraph employees and by what party they are run or to which party, directly or indirectly, they are affiliated ?

SHRI I. K. GUJRAL : If the hon. Member is referring to the unions which have been de-recognised, then the number is nine. It is difficult for me to say with certainty which union is connected with what political party, but the impression generally—(*Interruption*).

श्री जार्ज फरनेन्डीज : किसी राजनैतिक दल से किसी यूनियन का सम्बन्ध नहीं है लेकिन बाद में जो मान्यता दी है वह कांग्रेस की यूनियन को दी है।

SHRI I. K. GUJRAL : One thing that I would like to assert, and I think the hon. Member, if he helps me in this—(*Interruption*).

श्री जार्ज फरनेन्डीज : किसी यूनियन का सम्बन्ध राजनैतिक दल स नहीं है लेकिन आप ने कांग्रेस की यूनियन को मान्यता दी है।... (**व्यवधान**) . . . . . .

SHRI I. K. GUJRAL : I am willing to accept this : that the unions should not be associated with any political party, and that will be a good thing for trade unionism, when political parties stop taking interest.

श्री जार्ज फरनेन्डीज : सरदार वल्लभ भाई पटेल से शुरू हुआ है, क्या बात करते हो ?

SHRI G. M. BISWAS : Does the Minister know that the INTUC is directly an organ of the Congress ?

MR. SPEAKER : He is not answering. He will not be allowed to answer. Order, order.

श्री कंवरल लाल गुप्त : क्या यह बात सही है कि पोस्टल डिपार्टमेंट में सब से ज्यादा आदमी गिरफ्तार हुए और सबसे ज्यादा आदमियों के खिलाफ ऐक्शन लिए गए, गो स्लो में भी और पोस्टल स्ट्राइक के दिनों में भी ? अगर यह बात ठीक है तो इस के क्या कारण हैं और सवाल का दूसरा हिस्सा मेरा यह है कि आप ने यह सर्कुलर निकाला कि जो लोग गैरहाजिर रहे, उन्होंने उन दिनों में लोगों को उकसाया नहीं, कोई वायलेंस नहीं किया, कोई गड़बड़ नहीं की तो उन लोगों के ऊपर आप ने कार्यवाही छोड़ दी, जो की थी, वह वापस ले ली। तो क्या वह लोग जो बेकार ही गिरफ्तार कर लिए गए, जैसा मैंने कल बताया था, डाकखाने के वह लोग जो स्ट्राइक में नहीं थे और कुछ नहीं कर रहे थे, ऐसे लोग भी गिरफ्तार हुए, जो वायलेंस भी नहीं किए, किसी को भड़काए भी नहीं, क्या सरकार उनके खिलाफ कार्यवाही वापस करने पर विचार करेगी ?

SHRI I. K. GUJRAL : The first question that the hon. Member has raised is about the number of arrests having taken place. I might mention here that the strike has affected this department a degree more, because this department is the second biggest employer also in this country. The second thing that I would like to mention is that so far as the

arrests are concerned, those were matters concerned with the law and order authorities. The P & T does not come in; the arrests took place because some people may have infringed the law, and the cases are being tried in the courts and we are awaiting the judgment.

SHRI SRADHAKAR SUPAKAR : How far is it correct to say that a lot of these postal goods were destroyed in Delhi ? You will remember that 19th September was the date on which the summons to the MPs were issued and I have not yet received the summons, and I am supposed to be here unofficially without receiving the summons.

MR. SPEAKER : So we thank him for coming in spite of that. You would not receive the DA also now !

श्री सरजू पांडेय : अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि गो स्लो वर्क के सिलसिले में लगभग 200 आदमियों पर कार्यवाही की गई है, उसे वापस लेने का कोई प्रश्न नहीं है। तो क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि क्योंकि उनकी मांगें वाजिब थीं और उन्होंने कोई काम ऐसा नहीं किया, किसी हिंसात्मक कार्यवाही में हिस्सा नहीं लिया तो क्या मंत्री जी उस के ऊपर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हैं कि इस तरह की जितनी भी कार्यवाहियां की गई हैं वह वापस ले लें ?

SHRI I. K. GUJRAL : It was not for any demands. The go-slow tactics were resorted to for non-service matters. The JCA leaders were going on strike and they were resorting to go-slow. The question of slackening of discipline does not arise.

श्री ओंकार लाल बेरवा : अध्यक्ष महोदय, डाक तार विभाग के कर्मचारियों ने किसी तरह की तोड़फोड़ नहीं की थी तथा वे अपने दफ्तर में आ कर बैठ गये थे, ऐसे व्यक्तियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया था । क्या सरकार वे सारे मुकदमे वापस ले कर विभागीय जांच के बारे में सोच रही है ?

श्री इ० कु० गुजराल : अध्यक्ष महोदय, इसके लिये मैंने पहले भी अर्ज किया है

SHRI KANWAR LAL GUPTA : He is evading the issue.

अध्यक्ष महोदय, पहले मैंने भी और बेरवा जी ने भी यही पूछा है कि जो गिरफ्तारियां दफ्तर के अन्दर हुई हैं। जहां कोई कानून नहीं तोड़ा जा रहा था तथा वे हड़ताल पर भी नहीं थे, क्या उन के बारे में आप एन्कवायरी करेंगे कि आया ऐसा हुआ भी है या नहीं और अगर ऐसा हुआ है तो क्या उन के खिलाफ मुकदमे वापस लेंगे ।

SHRI I. K. GUJRAL : The hon. member has mentioned that people were arrested without breaking the law. I am unable to contribute to that way of thinking. The main point is, the law and order authorities came to the conclusion that people had broken the law and prosecuted them in court. It is for the judge to decide now.

श्री सीता राम केसरी : मैं जानना चाहता हूं कि स्ट्राइक ता० 19 के बारे में घोषित थी, क्या डाक तार विभाग के कर्मचारियों ने ता० 17 की रात से ही स्ट्राइक शुरू कर दी थी ? इस पर आपकी जानकारी क्या है ? अगर जानकारी थी तो क्या आपने कोई एक्शन लिया..... (**व्यवधान**)

SHRI I. K. GUJRAL : Some trouble had started in the RMS before 19th, but that was of a limited nature. (*Interruptions*). Hon. members on the other side by speaking loudly sometimes want to create the impression that they have got sympathy for the employees I want to assure the House and reiterate that the interests of the employees is supermost in our hearts.

SHRI TENNETI VISWANATHAN : The strike was after all a token strike, just like the token strike made by the Prime Minister yesterday. Why should the Government take a very serious notice of it ?

SHRI S. M. BANERJEE : Without commenting on the intelligence of Mr.

Gujral, I would request Dr. Ram Subhag to reply to this question. May I know whether it is a fact that the postal employees have been arrested only under section 188 of the IPC and section 5 of the ordinance. None of the cases involves moral turpitude ? As such will he kindly consider withdrawing the suspension notices till the court cases are decided and also take back the temporary employees who have not been given an opportunity to fight their court cases ?

SHRI I. K. GUJRAL : It is a request, not a question. If he wants a reply, the total number of people who had gone on strike in our department was 1.33 lakhs. The number of cases where action has been taken so far is only about 1100. That will show how lenient we are and what a compassionate attitude we are taking.

INFORMAL CONSULTATIVE COMMITTEE OF PARLIAMENT

98. SHRI BAL RAJ MADHOK : Will the Minister of PARLIAMENTARY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether any progress has been made to resolve the deadlock between the Government and the Opposition Parties regarding the functioning of Informal Consultative Committees of Parliament; and

(b) if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COMMUNICATIONS (DR. RAM SUBHAG SINGH): (a) and (b). The House was informed in reply to Starred Question No. 1054 on the 4th April, 1968 that the working of Informal Consultative Committees would be reviewed after the conclusion of one year. The position is under review.

SHRI BAL RAJ MADHOK : When it suits the ruling party these committees remain the close confine of the ruling party only, so that they cannot work effectively. But in private suggestions have been made and certain things have been said that these and these things will be done. May I know whether it is a fact that the government considers that these Committees can be made more effective if they are made formal and not informal ? When they are made formal they can meet regularly, not only during the session but also during intersession for longer periods. Then, whatever decisions are taken in these committees should be normally binding on the Ministries and the minutes and decisions taken at these meetings should be circulated among the members. May I know whether any such decisions have been taken or any such proposals are under the consideration of the government ?

DR. RAM SUBHAG SINGH : Actually, these committees are not the close preserve of the ruling party, as has been suggested by the hon. Member. Members belonging to various groups are attending these meetings.

श्री रवि राय : अभी तो सिर्फ रूलिंग पार्टी जाती है, हम लोग कोई नहीं जा रहे हैं, हम ने बायकाट किया हुआ है ।

DR. RAM SUBHAG SINGH : Actu- leader of the SSP would care to look at the attendance register he will see that every party has contributed to the working of these committees. As regards improvement in the working of these committees, we have advised all Ministries, excluding Defence, Atomic Energy and External Affairs that they should circulate the minutes of the meetings of the informal consultative committees to members. The Ministries were further advised that if on a particular issue there was a general consensus of opinion it should normally be accepted and, if there was any difficulty in doing so, the reasons for non-acceptance of that view should be explained to the members of the informal consultative committee. Over and above these two points, we have been taking particular care that the functioning of these committees is made more effective. As regards conveying the meeting during the inter-session period, we are not particular of having it only during the session time. Some committees, like the informal consultative committee, go to the spot and inspect projects and meet